CHAPTER-IV

AIACE IN MEDIA

दैनिक भास्कर

कोरबा 22-04-2021

कोल कर्मियों को राहत • कोयला कंपनियों को जारी किया सर्कुलर, सीजीएचएस पर होगा भुगतान

कोरोना के इलाज का भुगतान करेगी कोल इंडिया

भास्कर न्यूज़ | कोरबा

जिले में कंपनी का कोई अनुबंधित अस्पताल नहीं है, होती है परेशानी

कोरोना काल के दौरान कोल इंडिया प्रबंधन ने अपने करीब 2.70 लाख से ज्यादा कर्मचारियों, अधिकारियों व उनके परिजनों के उपचार कराने को लेकर बड़ी राहत दी है। कोल इंडिया के अधिकारी व कर्मचारी और उनके परिजन कोविड-19 से संक्रमित होने पर अब अपना इलाज कोल इंडिया से गैर अनुबंधित अस्पताल याने जो इंपैनल्ड अस्पताल नहीं हैं और आसपास क्षेत्र में हैं उन अस्पतालों में भी अपना उपचार करा सकेंगे। इलाज में आने वाली खर्च की राशि को वे कंपनी से रिम्बर्समेंट करा सकेंगे। कंपनी सीएचएस दर पर ही इलाज में खर्च होने वाली राशि का

कोल इंडिया ने अपने अधिकारी व कर्मचारियों के उपचार के लिए देशभर के 340 से ज्यादा बड़े अस्पतालों के साथ अनुबंध किया है। जहां उनको सीजीएचएस दर पर उपचार सुविधा मिलती है। लेकिन कोल इंडिया से अनुबंधित एक भी अस्पताल कोरबा जिले में नहीं है। इसके कारण कर्मचारियों को परेशानी होती है। जबकि प्रदेश के अन्य जिलों में बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़ के अस्पतालों में कोयला कर्मचारियों को उपचार मिलता है। अभी कोरोना के कारण समस्या और बढ़ गई है। निजी अस्पतालों में उपचार पर काफी खर्च हो रहा है। लेकिन कोल इंडिया के नए आदेश से जिले में काम करने वाले 15 हजार से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारी व उनके परिजनों को राहत मिलेगी।

भुगतान करेगी। कोरोना के कारण स्थिति बिगड़ चुकी है। कोल इंडिया के अधिकांश विभागीय अस्पतालों में सुविधाएं कम है। वहीं जो इंपैनल्ड याने अनुबंधित अस्पताल हैं वे प्रदेश व देश के अलग-अलग हिस्सों में स्थित है। कोरोना संक्रमित कर्मचारियों को दूर के अस्पताल तक ले जाने में भी दिक्कतें हो रही है। कई क्षेत्रों में लॉकडाउन भी है। इस विषम परिस्थितियों को देखते हुए कोयला अधिकारियों के संगठन एआईएसीई ने कोल इंडिया से मांग की थी कि जल्द गैर अनुबंधित अस्पतालों में उपचार की सुविधा दी जाए। जिसे कोल इंडिया ने मानते हुए किसी भी अस्पताल में कोरोना बीमारी का उपचार कराने पर सीजीएचएस दर पर रिम्बर्समेंट की सुविधा देने का आदेश जारी किया है। कोल इंडिया के ईडी (मेडिकल सर्विसेस) की ओर से एसईसीएल सहित अन्य कंपनियों को इसका आदेश जारी कर दिया गया है।

कोरोना संक्रमण से 451 कोयला कर्मियों की हो गयी मौत, पर अब तक यह तय नहीं कि मजदूरों को वैक्सीन कैसे मिलेगी !

सत्येंद्र कुमार ▷ धनबाद

कोरोना काल में भी देश को बिजली मिलती रहे, उद्योग-धंधे चलते रहें, इसके लिए कोयलाकर्मी दिन-रात एक किये हुए हैं. कार्य के दौरान वे वैश्विक महामारी कोरोना की चपेट में भी आ रहे हैं. आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, 17 मई, 2021 तक कोरोना से सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी अनुषंगी इकाइयों के 451 कर्मचारियों की मौत हो चुकी थी. आकड़ों के मुताबिक, 271 कोयला मजदूर, 68 बच्चों एवं पांच ठेका मजदूरों को जान गयी है. इनमें बीसीसीएल और सीसीएल के भी मजदूर हैं. बीसीसीएल के 20 और सीसीएल के 58 कर्मियों को जान गंवानी पड़ी.

• बाकी पेज 09 पर

संक्रमण का साया : विषम परिस्थिति में कार्य कर रहे कोल इंडिया व अनुषंगी कंपनियों के कर्मचारी

- मृतकों में कार्यरत कर्मियों के 121 बच्चे भी शामिल
- कोविड टीकाकरण के प्रति न तो कोल इंडिया गंभीर और न ही कोयला मंत्रालय
- कोयला उत्पादन से जुड़े कर्मियों को फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा भी नहीं

जानें कोल इंडिया का मैनपावर (अधिकारी समेत)

01 अप्रैल, 2020 तक	272445
01 अप्रैल, 2021 तक	259016

साल 2020 में किस कंपनी में कितनी मौत

कंपनी	कर्मी	बच्चे	ठेका कर्मी
बीसीसीएल	08	00	00
सीसीएल	20	00	00
इसीएल	16	06	01
एमसीएल	00	00	00
एनसीएल	08	09	01
एसइसीएल	49	21	00
डब्ल्यूसीएल	75	17	00
एनइसी	02	00	00
सीएमपीडीआइ	00	00	00
सीआइएल मुख्यालय	02	00	00
कुल	180	53	02

17 मई 2021 तक कहां कितनी मौत

कंपनी	कर्मी	बच्चे	ठेका कर्मी
बीसीसीएल	12	01	01
सीसीएल	38	09	00
इसीएल	26	03	01
एमसीएल	18	05	00
एनसीएल	41	27	01
एसइसीएल	86	11	01
डब्ल्यूसीएल	36	04	00
एनइसी	02	00	00
सीएमपीडीआइ	09	06	01
सीआइएल मुख्यालय	03	02	00
कुल	271	68	05

मृत बीसीसीएल कर्मियों के आश्रितों को 10 दिनों के अंदर मिलेगा पावना

धनबाद. कोरोना संक्रमण से मृत बीसीसीएलकर्मी के आश्रित को 10 दिनों के अंदर सभी तरह के पावना का भुगतान किया जायेगा. जीएमपी संतोष सिन्हा के हस्ताक्षर से जारी पत्र में सभी एरिया प्रबंधन को इस आशय का दिशा-निर्देश दिया गया है. आठ मई को हुई बैठक के आलोक में जारी निर्देश में श्री सिन्हा ने कहा है कि कोविड-19 से किसी कर्मचारी की मृत्यु होने के तीन दिन के अंदर एक्सग्रेसिया के तहत दी जाने वाली 15 लाख की राशि का कागजात बीसीसीएल मुख्यालय के कार्मिक उप प्रबंधक एनइइ के पास भिजवाना होगा, ताकि उसे मुख्यालय स्तरीय कमेटी के पास परीक्षण व अनुशंसा के लिए भेजा जा सके.

- आश्रित के नियोजन की फाइल तीन दिनों में पहुंचेगी मुख्यालय
- निधन के अगले दिन ही लाइफ कवर स्कीम की राशि का भुगतान

• बाकी पेज 09 पर

प्रभात खबर Fri, 21 May 2021
https://epaper.prabhatkhabar.com/c/60590429

हरिभूमि

जबलपुर - विराट भूमि

Date 22 May 2021

वेतन समझौते को लेकर लिखे गए पत्र की हरिद्वार सिंह ने की घोर निन्दा

राजनगर। ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल एग्जीक्यूटिव के प्रमुख महासचिव पी.के.सिंह राठौर के द्वारा कोयला कर्मचारियों के होने वाले 11 वें वेतन समझौता के संबंध में प्रश्न चिन्ह लगाते हुए। सचिव डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज को पत्र लिखकर कोयला कर्मचारियों के बेसिक का कोयला अधिकारियों के बेसिक से तुलना कर आपत्ति दर्ज की है। जिसमें उन्होंने कोयला कर्मचारियों का वेतन समझौता 10 वर्षों का किए जाने या कोयला कर्मचारियों का बेसिक कोयला अधिकारियों से अधिक ना हो पाने के संबंध में अपनी ओछी मानसिकता प्रकट की है। वह भी ऐसे में जब कोयला कर्मचारियों का 11वाँ वेतन समझौता हेतु सरकार द्वारा पत्र लिखकर कोल इंडिया प्रबंधन को जल्द ही जेबीसीसीआई समिति के गठन की कार्यवाही करने हेतु कहा गया है। पी.के.सिंह राठौर के द्वारा लिखे गए पत्र पर एसईसीएल एटक यूनियन के केंद्रीय महामंत्री, जेबीसीसीआई के वैकल्पिक सदस्य कामरेड हरिद्वार सिंह ने घोर निंदा व्यक्त की है। कामरेड हरिद्वार सिंह ने कहा कि इसके पूर्व ट्रेड यूनियनों द्वारा घोषित 2, 3 व 4 जुलाई 2020 की हड़ताल का पी.के.सिंह राठौर ने अपने संगठन के तरफ से पूर्ण समर्थन दिया था, जो की सराहनीय था। आज कर्मचारियों के वेतन समझौते को लेकर इस तरह का पत्र लिखना उन्हें शोभा नहीं देता है। गैर अधिकारी वर्ग में कर्मचारी को अ 1 ग्रेड तक पहुंचने में लगभग 15 से 20 वर्ष का समय लग जाता है। दूसरी तरफ अधिकारी वर्ग में आज सीधे ए 2 ग्रेड में नियुक्ति हो रही है। ऐसे में 20, 25 वर्षों तक कंपनी में कार्य किए एक उच्च ग्रेड के कर्मचारी के बेसिक की तुलना आज ज्वॉइन किए एक अधिकारी के बेसिक से तुलना करना कतई उचित नहीं है। कर्मचारी वर्ग का न्यूनतम बेसिक 1011.27 रुपए प्रतिदिन अथवा 26,293 रुपए प्रति माह है। वहीं दूसरी तरफ अधिकारी वर्ग के ए 1 ग्रेड का न्यूनतम बेसिक 40,000 हजार रुपए है। इसके अलावा अधिकारियों को कंपनी के द्वारा अन्य कई सुविधाएं मिलती हैं। अधिकारियों का पे रिवीजन कर्मचारियों या ट्रेड यूनियन के सहमति से नहीं होता है सरकार स्वतः ही पे रिवीजन करता है। कोयला कर्मचारियों का वेतन समझौता कोल इंडिया के उच्च प्रबंधन व ट्रेड यूनियन के आपसी सहमति से होता है जिस पर केंद्र सरकार की भी सहमति रहती है। कर्मचारियों के वेतन समझौते का जिक्र करने से बेहतर होता कि पी.के.सिंह राठौर अपनी मांगों को कोल इंडिया प्रबंधन अथवा कोयला मंत्रालय भारत सरकार के समक्ष रखते। इस तरह का पत्र लिखकर उन्होंने कर्मचारियों व अधिकारियों के बीच गहरी खाई खोदने का प्रयास किया है। जो कि कहीं से उचित नहीं है।

कर्मचारियों के वेतन समझौते को लेकर श्री पी.के.सिंह राठौर के द्वारा लिखे गए पत्र की एसईसीएल एटक यूनियन के केंद्रीय महामंत्री, जेबीसीसीआई के वैकल्पिक सदस्य कामरेड हरिद्वार सिंह ने की घोर निन्दा, जताई आपत्ति

जमुना कालरी २१ मई जमुना रजक - अनूपपुर ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल एग्जीक्यूटिव के प्रमुख महासचिव पी.के.सिंह राठौर के द्वारा कोयला कर्मचारियों के होने वाले 11 वें वेतन समझौता के संबंध में प्रश्न चिन्ह लगाते हुए सम्माननीय सचिव, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज को पत्र लिखकर कोयला कर्मचारियों के बेसिक का कोयला अधिकारियों के बेसिक से तुलना कर आपत्ति दर्ज की है, जिसमें उन्होंने कोयला कर्मचारियों का वेतन समझौता 10 वर्षों का किए जाने या कोयला कर्मचारियों का बेसिक कोयला अधिकारियों से अधिक ना हो पाने के संबंध में अपनी ओछी मानसिकता प्रकट की है, वह भी ऐसे में जब कोयला कर्मचारियों का 11वाँ वेतन समझौता हेतु सरकार द्वारा पत्र लिखकर कोल इंडिया प्रबंधन को जल्द ही जेबीसीसीआई समिति के गठन की कार्यवाही करने हेतु कहा गया है। पी.के.सिंह राठौर के द्वारा लिखे गए पत्र पर एसईसीएल एटक यूनियन के केंद्रीय महामंत्री, जेबीसीसीआई के वैकल्पिक सदस्य कामरेड हरिद्वार सिंह ने घोर निंदा व्यक्त की है। कामरेड हरिद्वार सिंह ने कहा कि इसके पूर्व ट्रेड यूनियनों द्वारा घोषित 2, 3 व 4 जुलाई 2020 की हड़ताल का श्री राठौर ने अपने संगठन के तरफ से पूर्ण समर्थन दिया था, जो की सराहनीय था। आज कर्मचारियों के वेतन समझौते को लेकर इस तरह का पत्र लिखना उन्हें शोभा नहीं देता है। गैर अधिकारी वर्ग में कर्मचारी को,-1 ग्रेड तक पहुंचने में लगभग 15 से 20 वर्ष का समय लग जाता है दूसरी तरफ अधिकारी वर्ग में आज सीधे 2 ग्रेड में नियुक्ति हो रही है ऐसे में 20, 25 वर्षों तक कंपनी में कार्य किए एक उच्च ग्रेड के कर्मचारी के बेसिक की तुलना आज ज्वॉइन किए एक अधिकारी के बेसिक से तुलना करना कतई उचित नहीं है। कर्मचारी वर्ग का न्यूनतम बेसिक 1011.27 रुपए प्रतिदिन अथवा 26,293 रुपए प्रति माह है। वहीं दूसरी तरफ अधिकारी वर्ग के 1 ग्रेड का न्यूनतम बेसिक 40,000 हजार रुपए है इसके अलावा अधिकारियों को कंपनी के द्वारा अन्य कई सुविधाएं मिलती हैं। अधिकारियों का पे रिवीजन कर्मचारियों या ट्रेड यूनियन के सहमति से नहीं होता है सरकार स्वत: ही पे रिवीजन करता है। कोयला कर्मचारियों का वेतन समझौता कोल इंडिया के उच्च प्रबंधन व ट्रेड यूनियन के आपसी सहमति से होता है जिस पर केंद्र सरकार की भी सहमति रहती है। कर्मचारियों के वेतन समझौते का जिक्र करने से बेहतर होता कि श्री राठौर अपनी मांगों को कोल इंडिया प्रबंधन अथवा कोयला मंत्रालय भारत सरकार के समक्ष रखते। इस तरह का पत्र लिखकर उन्होंने कर्मचारियों व अधिकारियों के बीच गहरी खाई खोदने का प्रयास किया है जो कि कहीं से उचित नहीं है। वर्तमान समय में जिस तरह से कोयला कर्मचारी बिना किसी अतिरिक्त लाभ के इस कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर सतत कार्य कर रहे हैं, कोयले का उत्पादन कर रहे हैं उनके वेतन समझौते पर आपत्ति किया जाना अनुचित है। एटक ट्रेड यूनियन इसकी घोर निन्दा करता है। वर्तमान में केंद्र सरकार की जो नीति कोल इंडिया व अन्य पब्लिक सेक्टर को लेकर है, वह किसी से छुपी नहीं है जैसे कामर्शियल माइनिंग, कोल इंडिया का शेयर बिक्री, सीएमपीडीआई को कोल इंडिया से अलग करना, कोल इंडिया का विखंडन, सीएमपीएफ का ईपीएफ में विलय, 30 वर्ष की सेवा या 50 वर्ष की उम्र के बाद जबरन सेवानिवृत्ति करने का फैसला आदि। कोल इंडिया को बचाने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि सभी ट्रेड यूनियन व अन्य एसोसिएशन मिलकर केंद्र सरकार की मजदूर व उद्योग विरोधी नीतियों का सामना करें, आपसी सामंजस्य बनाए रखें और तमाम मतभेदो से दूर रहें।

दैनिक भास्कर

कोरबा 25-05-2021

कंपनी से निकाले गए तो कोल अफसरों को दूसरी जगह भी नहीं मिलेगी नौकरी

भास्कर न्यूज | कोरबा

कोल इंडिया ने एसईसीएल सहित कंपनी के दूसरे अनुषांगिक कंपनियों में काम करने वाले करीब 16 हजार कोल अफसरों के लिए नया कोड ऑफ कंडक्ट डिसिप्लिन एंड अपील रुल बनाया है। जिसका सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। जिसके अनुसार अगर कोयला अधिकारी अगर लापरवाही व अनुशासन हीनता बरतते हैं, तो उनके लिए कठोर कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। कोयला कर्मचारियों को नौकरी से भी निकालने के साथ ही ऐसी कार्रवाई की जाएगी जिससे संबंधित अधिकारी को किसी अन्य कंपनी में भी नौकरी नहीं मिल पाएगा। कोल इंडिया ने नए कोड ऑफ कंडक्ट डिसिप्लिन एंड अपील रूल के अंतर्गत में मेजर व माइनर पेनाल्टी का नियम बनाया है। जिसमें अधिकारियों के खिलाफ की जाने वाले सामान्य कार्रवाई में कंपनी अधिकारियों के काम करने पर कुछ दिनों के लिए प्रतिबंध लगा सकता है।वेतन वृद्धि रोकने, प्रमोशन रोकने के अलावा संबंधित अधिकारी के वेतन व लीव इनकेशमेंट में भी कटौती किया जा सकेगा। अफसरों की लापरवाही के कारण अगर कोयला कंपनी को नुकसान होता है तो प्रबंधन ऐसे अधिकारी को डिमोशन भी कर सकती है।

जांच में हो नियमों का पालनः एएआईएसीई

कोयला अधिकारियों के संगठन एआईएसीई ने कोल इंडिया चेयरमैन को पत्र लिखा है। जिसमें अधिकारियों के खिलाफ किसी तरह की होने वाली जांच व अन्य कार्रवाई में नियमों का पालन करने की बात कही है। संयोजक पीके सिंह राठौर ने कहा कि सेंट्रल विजेलेंस कमीशन का नियम है कि अफसरों के खिलाफ कोई भी जांच 6 माह में कम्लीट करना चाहिए। लेकिन देखने को मिलता है कि इसमें काफी देरी होती है। इससे संबंधित अधिकारियों के अलावा प्रबंधन को भी नुकसान होता है। समय पर जांच होने से जो अधिकारी निर्दोष होते हैं उनकों जरुर राहत मिलेगी।

https://psuwatch.com/covid-aiace-urges-cil-to-hold-release-orders-for-promoted-e6-employees-in-abeyance

- In an order released on September 9, 2020, CIL had promoted E5 executives to E6 grade and had also announced their transfers
- However, the transferred executives were allowed to join at their present place of posting in view of the COVID-19 situation and the decision was to be reviewed in March

COVID: AIACE urges CIL to hold release orders for promoted E6 employees in abeyance

New Delhi: The All India Association of Coal Executives (AIACE) has urged the management of state-run Coal India Ltd (CIL) to keep in abeyance a release order issued by it for employees who have been promoted from E5 to E6 grade, considering the risk posed by the second wave of COVID-19 infections. In a letter addressed to Coal India Chairman and Managing Director (CMD) Pramod Agrawal, the AIACE said, “We shall like to highlight the fact that sensing the gravity of pandemic situation, even CIL has opted to postpone the Annual Coal Sock Measurement in SECL, WCL and MCL which was due to commence from 19th of April, 2021. In this month itself, many

employees and executives and their family members have lost their lives and many are still struggling for life."
"In this situation, the release order has not only created panic among affected executives but also on their family members and children," said the executives association.

In 2020, CIL promoted execs, but put hold on transfers due to COVID-19

In an order released on September 9, 2020, CIL had promoted E5 executives to E6 grade and had also announced their transfers. However, the transferred executives were allowed to join at their present place of posting in view of the COVID-19 situation and the management had said that the decision will be reviewed in March 2021. At a board meeting held on April 6, it was decided that Coal India and its subsidiaries will issue release orders for promoted employees within 10 days of an official order in this regard.

"These executives would have gladly accepted to be released by the time stipulated in this order, but suddenly our country has fallen in the grip of 2nd wave of Covid-19 pandemic which is stated to be three to four times deadlier and infectious than the virus prevailing last year. It may be recalled that the situation has drastically changed in the last one week, after CIL Board decided to execute these transfer orders," said the AIACE. It added, "Under the circumstances, we at AIACE are compelled to request you to keep in abeyance these release orders for a few weeks till the situation eases allowing safe inter-state movements, especially, when local level lockdowns have been imposed in different parts of the country."

The backdrop

The letter comes just days after Chhattisgarh-based CIL subsidiary South Eastern Coalfields Ltd (SECL) declared work from home (WFH) for employees as Bilaspur, along with several other districts in the state, was put under a lockdown to arrest the steep rise in COVID-19 infections. According to the Health Ministry, a total of 1,84,372 new cases were registered in the last 24 hours. Ten states, including Maharashtra, Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Delhi, Madhya Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Gujarat and Rajasthan have shown a rise in new COVID new cases. Around 82.04 percent of the new cases are reported from these 10 states.

https://psuwatch.com/covid-power-sector-employees-are-frontline-workers-coal-sector-employees-are-not

COVID: Power sector employees are frontline workers, but coal sector employees are not! Why?

Even as power sector employees have been designated by the govt as frontline workers, Coal PSU employees in CIL & SCCL are yet to be prioritised for COVID-19 vaccination

SHALINI SHARMA- MAY 15, 2021

- ***The Central government had asked state governments on April 27 to arrange a special vaccination drive to ensure that all power sector personnel***

- ***However, no such direction has been issued so far for coal sector employees***

New Delhi: Even as power sector employees have been designated by the government as frontline workers and a priority group for COVID-19 vaccination, employees in the coal sector in PSUs like Coal India Ltd (CIL) and Singareni Collieries Company Ltd (SCCL) are yet to be prioritised for vaccination. This is despite the fact that coal sector employees, just like their power sector counterparts, have been engaged in essential services through the course of the peaks of the COVID-19 pandemic. According to sources who spoke to PSU Watch on the condition of anonymity, Coal India Chairman and Managing Director Pramod Agrawal has also written a letter to the Ministry of Coal, urging the government to treat coal sector employees as frontline workers and facilitate procurement of COVID-19 vaccines for them on priority.

The issue has been highlighted by the All India Association of Coal Executives (AIACE) in a recent letter addressed to Prime Minister Narendra Modi. The AIACE has said that since coal is the prime source for meeting the country's energy requirement, it is imperative that PSU employees in CIL and SCCL be treated as frontline workers.

"Coal being the prime source of energy for country's needs, the employees of Coal India Ltd (CIL) and Singareni Collieries Company Ltd (SCCL) are doing their best to discharge their duties by observing COVID-19 protocols. Whole world was in safe zone at home during the lockdown, but coal sector employees were working. In this process, many employees and executives and their family members have lost their lives and many are still struggling for life," said AIACE principal general secretary PK Singh Rathor in the letter.

COVID-19: Govt has asked states to treat power sector employees as frontline workers

The Central government had asked state governments on April 27 to arrange a special vaccination drive to ensure that all power sector personnel, working in both private and public sector — generation, transmission and distribution utilities — are vaccinated. While noting that uninterrupted power supply is essential from the point of view of ensuring seamless public health service delivery and to allow people to avail services online, the Ministry of Power had said, “Therefore, it is imperative that the Power sector personnel, many of whom have to work in close proximity with each other and have public interfaces, remain protected from the infection, so that all three wings of power supply, namely generation, transmission and distribution are able to collectively provide 24x7 uninterrupted power supply.” In line with the direction, various power PSUs like NTPC, NHPC and Power Grid have carried out vaccination drives for their employees and their families.

However, no such direction has been issued so far for coal sector employees.

Over 5,400 employees at CIL COVID positive

In an official statement released on May 4, CIL had said that over 5,400 employees of the PSU had tested positive for COVID-19. The demand to treat CIL and SCCL employees as priority segment for COVID-19 vaccination comes close on the heels of the direction issued by the Ministry of Power for power sector personnel.

https://psuwatch.com/covid-aiace-once-again-asks-cil-management-to-hold-transfer-orders-e5-e6-promoted-employees

COVID: AIACE once again asks CIL to hold transfer orders for promoted E5-E6 employees

AIACE has once again urged the CIL management to hold transfer orders for promoted E5-E6 grade employees for a year in view of the second wave of COVID-19 infections

PSU WATCH BUREAU- MAY 19, 2021

- ***At least 64 of the promoted employees have been retained their existent place of posting, while 13 have foregone their promotion, said AIACE***
- ***In the letter, AIACE said that around 49 CIL employees, many of whom are old, diabetic and have hypertension, have applied for a stay on their transfer orders***

New Delhi: The All India Association of Coal Executives (AIACE) has once again urged the management of Coal India Limited (CIL) to hold inter-company transfer orders for promoted E5-E6 grade employees for a year in view of the second wave of COVID-19 infections. In a letter addressed to CIL Chairman and Managing Director (CMD) Pramod Agrawal, AIACE principal general secretary PK Singh Rathor said, "… it is requested to review the transfer order and keep it in abeyance for one year to help fight Covid-19 pandemic in a more meaningful way and save them (Coal India employees) and their family members from any tragedy."

Earlier in April, the AIACE had first urged the CIL management to hold transfer orders for promoted employees in the backdrop of a surge in COVID-19 infections. In the interim period, at least 64 of the promoted employees have been retained their existent place of posting, while 13 have foregone their promotion. In the letter, Rathor said that around 49 CIL employees, many of whom are old, diabetic and have hypertension, have applied for a stay on their transfer orders.

https://psuwatch.com/aiace-proposes-redesignation-of-grades-clubbing-of-discipline-for-promotion-at-cil

AIACE proposes re-designation of grades, clubbing of disciplines for promotion at CIL

AIACE has proposed changes to CIL's promotion process, re-designation of different grades and clubbing of disciplines for purpose of promotion to infuse motivation in the workforce

PSU WATCH BUREAU- MAY 28, 2021

AIACE proposes re-designation of grades, clubbing of disciplines for promotion at CIL

- The AIACE has proposed that semi-qualified employees, highest level non-executives be given a chance to be promoted to up to E3 grade on the basis of experience
- The proposal, if implemented, will be able to arrest frustration among executives/non-executive employees regarding career growth, said the association

New Delhi: The All India Association of Coal Executives (AIACE) has proposed changes to Coal India Ltd's (CIL) promotion process, re-designation of different grades and clubbing of disciplines for purpose of promotion from E5 to E6 grade onward along with redistribution of posts in various grades to infuse motivation among executives and staff of Coal India Ltd. In a letter addressed to CIL Chairman and Managing Director (CMD) Pramod Agrawal, AIACE principal general secretary PK Singh Rathor said, "It may be appreciated that in today's fast-paced world, if employees don't see equitable career growth, they become de-motivated and productivity is reduced. While it may not be possible for each staff to be promoted at

the same pace, employees should at least be given a chance to explore other roles within the organisation."

AIACE seeks promotion up to E3 grade for semi-qualified employees

The AIACE has proposed that semi-qualified employees/ Tech A grade/ office superintendent and highest level non-executive be given a chance to be promoted to up to E3 grade on the basis of experience. The association has proposed that semi-qualified employees be promoted to E1 grade on DPC basis after seven years of service in that grade and E2 grade again after seven years of service in E1 grade. "This step will be beneficial to both employees and the organisation. In such condition, non-executive employees will be motivated for promotion and exert more in their works and also the organisation will be able to meet the requirement of lower level Executives from internal arrangement and from departmental employees. In this way, dedicated and talented employees will have opportunity to at least reach E2 /E3 grade before retirement," said Rathor in the letter.

The AIACE has suggested to continue the present arrangement of promotion of departmental candidates by clearing departmental exam and direct promotion to E2 grade. "These candidates are eligible to reach up to E6 level if the age permits. Only E1 level executives should be made eligible for departmental exam and non-others for promotion to E2 grade and for promotion in E1 grade minimum experience in the company should be 15 years," the association said.

The pyramid of organisational structure

Adhering to the principle of pyramid of organisational structure, grade wise percentage of executive manpower and promotional avenues purely on vacancy basis may be kept as shown below, said the AIACE.

E1: 20% (By promotion from non-executives diploma holders in engineering, Inter ICWA/CA/CS and others) after serving at least 15 years in non-executive grade)

E2: 17% (7% by promotion from E1 grade after serving at least 10 years in E1 grade, 5% by promotion from E1 after clearing departmental exam and 5% through direct recruitment as Management Trainee)

E3: 15% (5% by promotion from E2 grade(diploma holders) having minimum 5 years experience in E2 grade, 5% by promotion from E2 who were promoted after clearing departmental exam and 5% from E2 who joined through direct recruitment as Management Trainee after one year of probation in E2 grade)

E4: 15% from E3 grade (direct recruits/those who were promoted through departmental exam) after completion of 5 years in E3

E5: 15% and promotion from E4 grade after completion of 5 years in E4

E6: 10% and promotion from E5 grade after completion of 5 years in E5

E7: 6% and promotion from E5 grade after completion of 5 years in E6

E8: 1.5 % and promotion from E7 grade after completion of 5 years in E7

E9: 0.5 % and promotion from E8 grade after completion of 1 year in E8

"… the above proposal, if implemented, will be able to arrest frustration among executives/non-executive employees regarding career growth. It will also create promotion avenue for semi-qualified employees (diploma holders in Engg and inter CA/ICWA/CS and others) up to E3 grade on the experience basis. As of now, the career of such employees is blocked which has created acute frustration and demoralisation in them," said the AIACE.

https://psuwatch.com/cil-tells-subsidiaries-to-ensure-1st-dose-of-covid-19-vaccination-for-employees-at-earliest

CIL tells subsidiaries to ensure 1st dose of COVID-19 vaccination for employees at earliest

CIL has issued an advisory to all its subsidiaries to tie up with private hospitals and ensure first dose of COVID-19 vaccination for its employees at the earliest

SHALINI SHARMA- JUNE 07, 2021

- ***First COVID-19 vaccine dose to be completed at the earliest and hence subsidiaries are advised to set up adequate number of vaccination centres, said CIL management***
- ***The cost incurred is to be borne by each coal subsidiary on their own***

New Delhi: State-run Coal India Limited (CIL) has issued an advisory to all its subsidiaries to tie up with private hospitals and ensure first dose of COVID-19 vaccination for its employees, contractual workers and eligible dependents at the earliest. In the official order, reviewed by PSU Watch, CIL's Executive Director (Medical) has said, "Subsidiaries of CIL, including CIL headquarters, may tie up with nearby private hospitals for ensuring vaccination of its employees, contractor workers (sic.) and eligible dependents."

The order comes weeks after PSU Watch reported that All India Association of Coal Executives (AIACE) principal general secretary PK Singh Rathor wrote a letter to Prime Minister Narendra Modi in May, urging the government to prioritise coal sector employees for COVID-19 vaccination.

First dose of COVID-19 vaccine should be administered at the earliest: CIL

The CIL management has directed its subsidiaries to ensure that the first dose of the COVID-19 vaccine is administered to all employees at the earliest. "First dose to be completed at the earliest and hence subsidiaries are advised to set up adequate number of vaccination centres to complete the first dose of vaccine. They are also advised to plan for the second dose of vaccine as per the planned schedule drawn in line with Government guidelines as revised by the Government from time to time," said the CIL advisory.

The tie-up with private hospitals is to be done in addition to the existing health facilities set up by CIL and its subsidiaries for COVID care. The cost incurred is to be borne by each coal subsidiary on their own.

The backdrop

In April, power sector employees were designated by the government as frontline workers and a priority group for COVID-19 vaccination, however, employees in the coal sector in PSUs like Coal India Ltd (CIL) and Singareni Collieries Company Ltd (SCCL) were not declared a priority group for COVID-19 vaccination. This is despite the fact that coal sector employees, just like their power sector counterparts, have been engaged in essential services through the course of the peaks of the COVID-19 pandemic.